



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, सोमवार, 14 मार्च, 2005/23 फाल्गुन, 1926

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला-171004, 14 मार्च, 2005

संख्या वि० स०-विधायन-गवर्नमेंट बिल/1-20-2005.—हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट

प्रबन्ध विधेयक, 2005 (2005 का विधेयक संख्यांक-4) जो आज दिनांक 14 मार्च, 2005 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्व-साधारण की सूचनाओं राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

जे० आर० गाजटा,
सचिव।

2005 का विधेयक संख्यांक 4

हिमाचल प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध विधेयक, 2005

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

राजस्व घाटे को उत्तरोत्तर कम करने तथा राजकोषीय स्थिरता से संगत ऋण प्रबन्धन, राज्य सरकार की राजकोषीय सक्रियताओं में अत्यधिक उत्तरदायित्व तथा मध्यम अवधि राजकोषीय नीति के संचालन द्वारा राजकोषीय प्रबन्ध तथा राजकोषीय स्थिरता में व्यवहार कुशलता सुनिश्चित करने के लिए तथा इससे सम्बन्धित या इसके आनुषंगिक विषयों के लिए राज्य सरकार के उत्तरदायित्व का उन्वय करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के छपनवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

अध्याय-1

प्रारम्भिक

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध अधिनियम, 2005 है।

संक्षिप्त
नाम और
प्रारम्भ।

(2) यह ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

2. इस अधिनियम में जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

परिभाषाएं।

(क) “बजट” से, संविधान के अनुच्छेद 202 के अधीन राज्य विधान सभा में रखा गया वार्षिक वित्तीय विवरण अभिप्रेत है ;

(ख) “चालू वर्ष” से, आगामी वर्ष का पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष अभिप्रेत है ;

(ग) “ऋण प्राप्ति” का वही अर्थ होगा जो निम्नलिखित तथा महालेखा परीक्षक द्वारा राज्य के वित्त लेखों में प्रयुक्त है ;

(घ) “आगामी वर्ष” से, वह वित्त वर्ष अभिप्रेत है जिसके लिए बजट प्रस्तुत किया जाना है ;

(ङ) “वित्तीय वर्ष” से, अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारम्भ होने वाला वर्ष अभिप्रेत है ;

(च) “राजकोषीय सूचकां” से, ऐसे परिमाण की संख्यात्मक अधिकतम सीमा और कुल राज्य घरेलू उत्पाद जो राज्य सरकार की राजकोषीय स्थिति के मूल्यांकन के लिए विहित किए जाएं, अभिप्रेत हैं ;

(छ) “राजकोषीय घाटा” से, वित्तीय वर्ष के दौरान ऋण के पुनःसंचाद, ऋण प्राप्तियों को अपवर्जित करके, संवित्त निधि में कुल प्राप्तियों से अधिक को

अपवर्जित करके, राज्य की संचित निधि से कुल संवितरण का अधिकतम अभिप्रेत है ;

स्पष्टीकरण.—राजकोषीय घाटे की संगणना करने के प्रयोजन के लिए, पब्लिक सेक्टर अनुक्रमों द्वारा उधार लेना और विशेष प्रयोजन यानों तथा अन्य समतुल्य उपकरणों, जहां पुनः संदाय का दायित्व राज्य सरकार पर हो, राज्य सरकार द्वारा उधार लिया गया माना जाएगा ।

(ज) "विहित" से, अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ;

(झ) "राजस्व घाटा" से, राजस्व खर्चों और राजस्व प्राप्तियों के मध्य अन्तर अभिप्रेत है ;

(ञ) "राज्य" से, हिमाचल प्रदेश राज्य अभिप्रेत है ; और

(ट) "राज्य सरकार" से, हिमाचल प्रदेश राज्य की सरकार अभिप्रेत है ।

अध्याय-2

विधान सभा में मध्यम अवधि राजकोषीय योजना रखना, राजकोषीय प्रबन्ध सिद्धान्त और लक्ष्य तथा अनुपालन प्रवर्तित करने के उपाय ।

मध्यम अवधि
राजकोषीय
योजना का
विधान
मण्डल के
समक्ष रखा
जाना ।

3. (1) मध्यम अवधि राजकोषीय योजना निम्नलिखित से सम्बन्धित प्रोत्साहनीय निर्धारण के अन्तर्गत होगी,—

(क) राजस्व प्राप्तियों और राजस्व खर्चों के मध्य अतिशेष ;

(ख) उत्पादनकारी आस्तियों के उत्पादन हेतु उधार सहित पूंजीगत प्राप्तियों का उपयोग ;

(ग) पूर्ववर्ती वर्ष में विहित राजकोषीय सूचकों के प्रदर्शन के मूल्यांकन के मुकाबले में पूर्वतम उपवर्णित लक्ष्य और पुनरीक्षित प्राक्कलनों के अनुसार चालू वर्ष में संभाव्य प्रदर्शन ;

(घ) राज्य सरकार की राजकोषीय स्थिति को प्रभावित करने वाली हाल ही की आर्थिक प्रवृत्तियों और उत्पादन तथा विकास के लिए भविष्य की संभाव्यता पर एक विवरण ; और

(ङ) आगामी वित्तीय वर्ष के लिए राजकोषीय क्षेत्र में राज्य सरकार की सामरिक प्राथमिकताएं ।

(2) मध्यम अवधि राजकोषीय योजना विहित राजकोषीय सूचकों के लिए अन्तर्निहित धारागाओं के विनिर्देश सहित एक चार वर्षीय चल (रोलिंग) लक्ष्य आरम्भ करेगी ।

(3) राज्य सरकार प्रत्येक वित्तीय वर्ष में, राज्य विधान सभा के समक्ष वार्षिक बजट सहित मध्यम अवधि राजकोषीय योजना प्रस्तुत करेगी ।

(4) मध्यम अवधि राजकोषीय योजना ऐसे प्ररूप में होगी, जैसी विहित की जाए ।

4. (1) राज्य सरकार, राजस्व घाटे को कम करने और राजकोषीय स्थिरता के साथ ऋण के संगत प्रबन्ध (व्यवस्था) के लिए समुचित उपाय करेगी।

राजकोषीय
प्रबन्ध
सिद्धान्त।

(2) राज्य सरकार को निम्नलिखित राजकोषीय प्रबन्ध सिद्धान्तों द्वारा मार्गदर्शित किया जाएगा, अर्थात् :—

- (क) राज्य सरकार के ऋण का प्रज्ञायुक्त स्तरों पर अनुरक्षण करना ;
- (ख) ऐसे दायित्वों के गुणों और स्तर के विशिष्ट सन्दर्भ सहित प्रतिभूतियों तथा अन्य समाश्रित दायित्वों का समझ-बूझ से प्रबन्ध करना ;
- (ग) यह सुनिश्चित करना कि राज्य सरकार के नीति विनिश्चयों का भावी पीढ़ियों द्वारा उनकी वित्तीय विवक्षाओं पर सम्यक् ध्यान रहे ;
- (घ) कर के घाटे के स्तर में स्थायित्व और पूर्वसूचनीयता की युक्तियुक्त भासा को सुनिश्चित करना ;
- (ङ) विशेष प्रोत्साहनों, रियायतों और छूटों में कमी करके कर प्रणाली की समग्रता कायम रखना ;
- (च) आर्थिक कार्यकुशलता और अनुपालन लागत का सम्यक् ध्यान रखते हुए कर नीतियों को आगे बढ़ाना ;
- (छ) वसूली लागत और साम्या का सम्यक् ध्यान रखते हुए गैर-कर राजस्व नीतियों को आगे बढ़ाना ;
- (ज) यह सुनिश्चित करना कि राज्य सरकार की भौतिक आस्तियों का उचित तौर से अनुरक्षण हो रहा है ; और
- (झ) पर्याप्त जानकारी प्रकट करके राजकोषीय योजना और लोक वित्त की स्थिति के संचालन की संवीक्षा (जांच) के लिए जनसाधारण को अनुज्ञात करना।

5. (1) विशिष्टियों और पूर्वगामी उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, राज्य सरकार निम्न प्रयास करेगी—

राजकोषीय
प्रबन्ध लक्ष्य।

- (क) कुल राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत का राजस्व घाटा पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष से कम से कम दो प्रतिशत (बिन्दु) कम करना जब तक कि राजस्व अतिशेष उपार्जित नहीं हो जाता ;
- (ख) दीर्घकालिक ऋण पर इसकी परादेय प्रतिभूतियों को अधिकाधिक घटाना, जब तक कि यह परादेय जोखिम भारित प्रत्याभूति को पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल राजस्व प्राप्तियों के अस्सी प्रतिशत तक समाप्त न कर दे, जिसके लिए वित्त लेखों के अनुसार वास्तविक उपलब्ध है।

(2) उप-धारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, यथास्थिति, राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा या प्राकृतिक विपदा की घोषणा करने या ऐसे अन्य असाधारण आधार जैसे राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं के कारण

राज्य सरकार के वित्त प्रबन्ध पर अपूर्वदृश्य मांगों की दशा में राजस्व घाटे में बढ़ोतरी हो सकती है :

परन्तु इस उप-धारा के अधीन विनिर्दिष्ट आधार या आधारों के बारे में ऐसे घाटे की रकम के उपरोक्त लक्ष्यों से अधिक होने के पश्चात् विवरण यथाशक्य शीघ्र विधान सभा के समक्ष रखा जाएगा।

राजकोषीय
पारदर्शिता
के लिए
उपाय।

6. (1) राज्य सरकार, लोक हित में अपने राजकोषीय प्रचालन में बेहद पार-पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए युक्तियुक्त उपाय करेगी और वार्षिक बजट तैयार करने में यथासाध्य गोपनीयता कम करेगी :

परन्तु राज्य सरकार को किसी ऐसी सूचना को रोकने की शक्ति होगी जिससे राजकोष के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो।

(2) विशेषतया और पूर्वगामी उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, राज्य सरकार, वार्षिक बजट पेश करते समय कथन में ऐसे प्ररूप में जैसा विहित किया जाए, निम्नलिखित प्रकट कर सकेगी,

(क) लेखा मानकों, नीतियों और विहित राजकोषीय सूचकों की संगणना को प्रभावित करने वाले या प्रभावित करने की सम्भावना, में महत्वपूर्ण परिवर्तन; और

(ख) लोक हित के यथा साध्य और संगत, प्रत्याभूतियों के रूप में सृजित आकस्मिक दायित्वों, पब्लिक सेक्टर उपक्रमों द्वारा उधारों में से उद्भूत वास्तविक दायित्वों और विशेष प्रयोजन यानों तथा अन्य समतुल्य लिखतों, जहां प्रतिसंदाय के लिए दायित्व राज्य सरकार पर हो, राज्य सरकार द्वारा किए गए सभी दावे और प्रतिबद्धताएं जो संभावी बजट विवक्षाएं रखती हों।

अनुपालन
प्रवर्तित करने
के
उपाय।

7. (1) वित्त विभाग का प्रभारी मन्त्री प्रत्येक छह मास के पश्चात्, बजट से सम्बन्धित प्राप्तियों और व्यय की प्रवृत्ति का पुनर्विलोकन करेगा और ऐसे पुनर्विलोकन का निष्कर्ष विधान सभा के समक्ष रखेगा। पुनर्विलोकन रिपोर्ट ऐसे प्ररूप में होगी जैसा विहित किया जाए और निम्नलिखित को स्पष्ट करेगी,—

(क) इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार पर बाध्यताओं को बहन करने में किसी विचलन या संभाव्य विचलन को संत्यक्त करना ;

(ख) क्या ऐसा विचलन सारभूत है और वास्तविक या संभाव्य बजट के परिणामों से सम्बन्धित है और राज्य सरकार द्वारा साधारण आर्थिक पर्यावरण और नीति परिवर्तनों के कारण अधिक विचलन को माना जा सकता है ; और

(ग) राज्य सरकार द्वारा लिए जाने वाले प्रस्तावित-उपचारी उपाय।

(2) जब कभी राज्य सरकार की किसी नई नीति के विनिश्चय के कारण दिए गए वर्ष के लिए पूर्व विनिर्दिष्ट स्तरों पर राजस्व में या तो कमी या व्यय के बढ़ने के आसार हों, जो राज्य सरकार या इसके पब्लिक सेक्टर उपक्रमों को प्रभावित करें, तो राज्य सरकार ऐसे नीति विनिश्चय लेने से पूर्व, विधान सभा द्वारा अधिनियमित किसी अधिनियम के अधीन राज्य की समेकित निधि से संदत्त की जाने वाली या को लागू होने वाली या में से प्राधिकृत रकमों को कम करके चालू और आगामी वित्तीय वर्षों के लिए राजकोषीय समाधान के पणतः प्रतिकार के लिए ऐसी राशियों के विनियोग हेतु उपबन्ध करके या राजस्व में वृद्धि के लिए अन्तरिम उपायों को करके या दोनों को मिला कर, उपाय करेगी :

परन्तु इस उप-धारा की कोई बात संविधान के अनुच्छेद 202 के खण्ड (3) के अधीन राज्य की संवेक्ति निधि पर प्रभावित व्यय को लागू नहीं होगी।

8. (1) राज्य सरकार, इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए, नियम बनाने की शक्तियां।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबन्ध कर सकेंगे, अर्थात् :—

(क) धारा 3 की उप-धारा (4) के खण्ड (क) के अधीन राज्य सरकार की राजकोषीय स्थिति के मूल्यांकन के लिए उपाय ;

(ख) धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन मध्यम अवधि राजकोषीय प्लान का स्वरूप ;

(ग) धारा 6 की उप-धारा (2) के अधीन प्रकटीकरण के लिए विवरणों का स्वरूप ; और

(घ) धारा 7 की उप-धारा (1) के अधीन पुनर्विलोकन रिपोर्ट का स्वरूप।

9. इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, विधान सभा के समक्ष, जब यह सत्र में हो, कुल चौदह दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी और यदि, सत्र जिसमें यह ऐसे रखा गया है या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के अवसान से पूर्व विधान सभा इस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाए या विधान सभा सहमत हो जाए कि यह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए, तो तत्पश्चात्, यथास्थिति, नियम केवल ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा या निष्प्रभाव हो जाएगा, किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई या की जाने से छोड़ी गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

नियमों का विधान मण्डल के समक्ष रखा जाना।

10. इस अधिनियम या तदधीन बनाए गए नियमों के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही राज्य सरकार या इसके किसी अधिकारी के विरुद्ध नहीं होगी।

सद्भावपूर्वक की गई कार्यवाही के लिए संरक्षण।

11. इस अधिनियम के उपबन्ध, इसके अतिरिक्त होंगे, और तत्समय प्रवृत्त अन्य किसी विधि के उपबन्धों के अन्वयिकरण में नहीं होंगे।

अन्य विधियों को लागू करने पर बर्जन नहीं।

कठिनाईयों
को दूर
करने की
शक्ति ।

12. (1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो राज्य सरकार आदेश द्वारा ऐसे उपबन्ध, जो इस अधिनियम के उपबन्धों के साथ, असंगत न हों, जो कठिनाई दूर करने के लिए आवश्यक प्रतीत होते हों, राजपत्र में प्रकाशित कर सकेगी ।

(2) उप-धारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, इसके बनाए जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र विधान सभा के समक्ष रखा जाएगा ।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

पिछले कई वर्षों से राज्य की वित्तीय स्थिति अत्यधिक खराब हुई है। राज्य की वित्तीय स्थिति का इस प्रकार खराब होना चिन्ता का विषय है। इसलिए ऐसी खराब होती वित्तीय स्थिति पर विधि अधिनियमित करके रोक लगाना अनिवार्य समझा गया है। विधेयक राजकोषीय प्रबंध और राजकोषीय स्थिरता में सावधानी (प्रज्ञा) के लिए मार्गदर्शन करके और राज्य सरकार को, राजकोषीय कठिनाईयों, राजस्व घाटे को कम करने, राजकोषीय स्थिरता के साथ संगत राज्य ऋणों का प्रबंध करने के लिए उठाए गए पगों को विनिर्दिष्ट करने वाली मध्यम अवधि राजकोषीय योजना को और राज्य सरकार के राजकोषीय प्रचालन में अत्यधिक पारदर्शिता लाने के बारे में, राज्य विधान सभा के समक्ष लाने को समर्थ बनाता है।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

वीरभद्र सिंह,
मुख्य मंत्री।

शिमला :

तारीख....., 2005.

वित्तीय ज्ञापन

विधेयक के उपबन्ध अधिनियमित होने पर, विद्यमान सरकारी तन्त्र द्वारा प्रवर्तित किए जाएंगे। इस प्रकार इनसे राजकोष पर कोई अतिरिक्त व्यय उपगत नहीं होगा।

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

विधेयक का खण्ड 8, राज्य सरकार को इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यन्वित करने के लिए नियम बनाने के लिए सशक्त करता है। यह प्रत्यायोजन आवश्यक और सामान्य स्वरूप का है।

हिमाचल प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध विधेयक, 2005

राजस्व घाटे को उत्तरोत्तर कम करने तथा राजकोषीय-स्थिरता से संगत ऋण प्रबन्धन, राज्य सरकार की राजकोषीय सक्रियताओं में अत्यधिक पारदर्शिता तथा मध्यम अवधि राजकोषीय नीति के संचालन द्वारा राजकोषीय प्रबन्ध तथा राजकोषीय स्थिरता में व्यवहार कुशलता सुनिश्चित करने के लिए तथा इससे सम्बन्धित या इसके अनुषंगिक विषयों के लिए राज्य सरकार के उत्तरदायित्व का उपबन्ध करने के लिए विधेयक ।

वीरभद्र सिंह,
मुख्य मन्त्री ।

सुरेन्द्र सिंह ठाकुर,
सचिव (विधि) ।

शिमला :

तारीख....., 2005.

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 4 of 2005.

**THE HIMACHAL PRADESH FISCAL RESPONSIBILITY AND BUDGET
MANAGEMENT BILL, 2005**

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

to provide for the responsibility of the State Government to ensure prudence in fiscal management and fiscal stability by progressive reduction of revenue deficit and debt management consistent with fiscal stability, greater transparency in fiscal operations of the State Government and conduct of fiscal policy in a medium term fiscal framework and for matters connected therewith or incidental thereto.

Be it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Fifty-sixth Year of the Republic of India, as follows:—

CHAPTER-I

PRELIMINARY

1. (1) This Act may be called the Himachal Pradesh Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2005.

Short title
and
commence-
ment.

(2) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the Official Gazette, appoint.

2. In this Act, unless the context otherwise requires,—

Definitions.

(a) “budget” means the Annual Financial Statement laid before the State Legislative Assembly under article 202 of the Constitution ;

(b) “current year” means the financial year preceding the ensuing year ;

(c) “debt receipt” shall have the same meaning as used in the finance accounts of the State by Comptroller and Auditor General ;

(d) “ensuing year” means the financial year for which the budget is being presented ;

(e) “financial year” means the year commencing on the first day of April ;

(f) “fiscal indicators” means the numerical ceilings and proportions to gross state domestic product, of such measures, as may be prescribed, for evaluation of the fiscal position of the State Government ;

- (g) "fiscal deficit" means the excess of total disbursements from the Consolidated Fund of the State, excluding repayment of debt, over total receipts into the Consolidated Fund, excluding the debt receipts, during a financial year ;

Explanation.—For the purpose of calculation of fiscal deficit, borrowings by Public Sector Undertakings and Special Purpose Vehicles and other equivalent instruments, where the liability for repayment is on the State Government are to be treated as borrowings of the State Government.

- (h) "prescribed" means prescribed by the rules made under this Act ;

- (i) "revenue deficit" means the difference between revenue expenditure and revenue receipts ;

- (j) "State" means the State of Himachal Pradesh ; and

- (k) "State Government" means the Government of Himachal Pradesh.

CHAPTER-II

LAYING OF MEDIUM TERM FISCAL PLAN IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY, FISCAL MANAGEMENT PRINCIPLES AND TARGETS AND MEASURES TO ENFORCE COMPLIANCE.

Medium term fiscal plan to be laid before the Legislature.

3. (1) The medium term fiscal plan shall include an assessment of sustainability relating to,—

- (a) the balance between revenue receipts and revenue expenditures ;
- (b) use of capital receipts including borrowings for generating productive assets ;
- (c) an evaluation of the performance of the prescribed fiscal indicators in the previous year *vis-a-vis* the targets set out earlier, and the likely performance in the current year as per revised estimates ;
- (d) a statement on the recent economic trends and future prospects for growth and development affecting fiscal position of the State Government ; and
- (e) the strategic priorities of the State Government in the fiscal area for the ensuing financial year.

- (2) The medium term fiscal plan shall set forth a four year rolling target for the fiscal indicators prescribed, with specification of underlying assumptions.

(3) The State Government shall in each financial year lay before the State Legislative Assembly a medium term fiscal plan along-with the annual budget.

(4) The medium term fiscal plan shall be in such form as may be prescribed.

4. (1) The State Government shall take appropriate measures to reduce the revenue deficit and manage the debt consistent with fiscal stability.

Fiscal management principles.

(2) The State Government shall be guided by the following fiscal management principles, namely:—

- (a) to maintain State Government debt at prudent levels;
- (b) to manage guarantees and other contingent liabilities prudently with particular reference to the quality and level of such liabilities ;
- (c) to ensure that policy decisions of the State Government have due regard to their financial implications on future generations;
- (d) to ensure a reasonable degree of stability and predictability in the level of the tax burden;
- (e) to maintain the integrity of the tax system by minimizing special incentives, concessions and exemptions ;
- (f) to pursue tax policies with due regard to economic efficiency and compliance costs ;
- (g) to pursue non-tax revenue policies with due regard to cost recovery and equity ;
- (h) to ensure that physical assets of the state Government are properly maintained; and
- (i) to disclose sufficient information to allow the public to scrutinize the conduct of fiscal policy and the state of public finances.

5. (1) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing provisions, the State Government shall endeavour to—

Fiscal management targets.

- (a) reduce revenue deficit as percentage of total revenue receipts by at least two percentage points from the previous financial year until revenue balance is achieved;
- (b) progressively reduce its outstanding guarantees on long term debt, until it can cap outstanding risk weighted guarantees at eighty per cent of total revenue receipts in the preceding financial year for which actuals are available as per finance accounts.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), the revenue deficit may be exceeded in the case of unforeseen demands on the finances of the State Government due to reasons of national security or natural calamity declared by the State Government or the Central

Government, as the case may be, or such other exceptional grounds, as may be specified by the State Government:

Provided that a statement in respect of the ground or grounds specified under this sub-section shall be placed before the Legislative Assembly as soon as may be, after such deficit amount exceeds the aforesaid targets.

Measures
for fiscal
transpa-
rency.

6. (1) The State Government shall take suitable measures to ensure greater transparency in its fiscal operations in public interest and minimize as far as practicable, secrecy in the preparation of the annual budget :

Provided that the State Government shall have the power to withhold any such information, which would adversely affect the interest of the State Exchequer.

(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing provisions, the State Government shall, at the time of presentation of the annual budget, disclose in a statement in the form, as may be prescribed,—

(a) the significant changes in the accounting standards, policies and practices affecting or likely to affect the computation of prescribed fiscal indicators; and

(b) as far as practical and consistent with public interest, the contingent liabilities created by way of guarantees, the actual liabilities arising out of borrowings by Public Sector Undertakings and Special Purpose Vehicles and other equivalent instruments where liability for repayment is on the State Government, all claims and commitments made by the State Government having potential budgetary implications.

Measures to
enforce co-
mpliance.

7. (1) The Minister-in-charge of the Department of Finance shall review, after every six months, the trends in receipts and expenditure in relation to the budget, and place before the Legislative Assembly the outcome of such reviews. The review report shall be in such form as may be prescribed and shall explain,—

(a) any deviation or likely deviation in meeting the obligations cast on the State Government under this Act;

(b) whether such deviation is substantial and relates to the actual or the potential budgetary outcomes, and how much of the deviation can be attributed to general economic environment and to policy changes by the State Government ; and

(c) the remedial measures the State Government proposes to take.

(2) Whenever there is a prospect of either shortfall in revenue or excess of expenditure over pre-specified levels for a given year on account of any new policy decision of the State Government that affects either the State Government or its Public Sector Undertakings, the State Government, prior to taking such policy decision, shall take measures to fully offset the fiscal impact for the current and future financial years by curtailing the sums authorized to be paid and applied from and out of the

Consolidated Fund of the State under any Act enacted by the Legislative Assembly to provide for the appropriation of such sums, or by taking interim measures for revenue augmentation, or by taking up a combination of both:

Provided that nothing in this sub-section shall apply to the expenditure charged on the Consolidated Fund of the State under clause (3) of article 202 of the Constitution.

8. (1) The State Government may, by notification in the Official Gazette, make rules for carrying out the provisions of this Act.

Powers to make rules.

(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for all or any of the following matters, namely:—

- (a) the measures for evaluation of the fiscal position of the State Government under clause (a) of sub-section (4) of section 3;
- (b) the form of medium term fiscal plan under sub-section (1) of section 3;
- (c) the form of statements for disclosure under sub-section (2) of section 6 ; and
- (d) the form of review report under sub-section (1) of section 7.

9. Every rule made under this Act shall be laid, as soon as may be after it is made, before Legislative Assembly, while it is in session, for a total period of 14 days, which may be comprised in one session or in two or more successive sessions and if, before the expiry of the session in which it is so laid or the successive sessions as aforesaid, the Legislative Assembly agrees in making any modification in the rule or Legislative Assembly agrees that the rule should not be made, the rule shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of any thing previously done or omitted to be done under that rule.

Rules to be laid before the Legislature.

10. No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against the State Government or any of its officers for anything which is in good faith done or intended to be done under this Act or the rules made thereunder.

Protection of action taken in good faith.

11. The provisions of this Act shall be in addition to, and not in derogation of, the provisions of any other law for the time being in force.

Application of other laws not barred.

12. (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may, by order published in the Official Gazette, make such provisions, not inconsistent with the provisions of this Act, as may appear to be necessary for removing the difficulty.

Power to remove difficulties.

(2) Every order made under sub-section (1) shall be laid, as soon as may be after it is made, before the Legislative Assembly.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Over the years, State finances have seen considerable deterioration. This deterioration in State finances has been a matter of concern. As such, it has been considered essential to put a cap on such a deteriorating condition of State finances by enacting a law. This Bill seeks to address the issue by laying down a roadmap for bringing about prudence in fiscal management and fiscal stability and enable the State Government to bring before the State Legislative Assembly, a medium term fiscal plan specifying the steps being taken to address the fiscal difficulties, reduce revenue deficit, manage State debt consistent with fiscal stability and bring about a greater transparency in the fiscal operations of the State Government.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

VIRBHADRA SINGH,
Chief Minister.

SHDMLA :

The....., 2005.

FINANCIAL MEMORANDUM

The provisions of the Bill, when enacted, shall be enforced through the existing Government machinery. As such, there shall be no additional expenditure out of the State Exchequer.

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

Clause 8 of the Bill seeks to empower the State Government to make rules for carrying out the provisions of this Act. This delegation is essential and normal in character.

**THE HIMACHAL PRADESH FISCAL RESPONSIBILITY AND BUDGET MANAGEMENT
BILL, 2005**

A

BILL

to provide for the responsibility of the State Government to ensure prudence in fiscal management and fiscal stability by progressive reduction of revenue deficit and debt management consistent with fiscal stability, greater transparency in fiscal operations of the State Government and conduct of fiscal policy in a medium term fiscal framework and for matters connected therewith or incidental thereto.

VIRBHADRA SINGH,
Chief Minister.

SURINDER SINGH THAKUR,
Secretary (Law).

SHIMLA :

The , 2005.

